

गूँज के सरी

(हिन्दी साप्ताहिक)

RNI NO. - UTTHIN/2023/88849

वर्ष: 04

अंक: 26

देहरादून, मंगलवार 13 अक्टूबर 2026

मूल्य : 2 रुपये प्रति

पृष्ठ: 4

कन्या पूजन तभी सार्थक, जब बेटियों को मिले सम्मान, सुरक्षा और आगे बढ़ने के समान अवसर : मुख्यमंत्री

देहरादून (ब्यूरो)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून स्थित आईआरटीडी प्रेक्षागार में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर आयोजित 'बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम' में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड बोर्ड की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 149 मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सभी मेधावी बालिकाओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस और शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस एक साथ होना विशेष संयोग है। भारतीय संस्कृति में सदियों से कन्याओं को शक्ति का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है। नंदा गौरा योजना के अंतर्गत बेटों के जन्म पर 11 हजार रुपये तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना से अब तक चार लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के माध्यम से माताओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और पोषण पर विशेष ध्यान दिया

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर मुख्यमंत्री ने 149 मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन प्रदान कर किया सम्मानित



जा रहा है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में जीवनयापन करने वाले बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि कोई भी बेटा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा एक से 12वीं तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना और गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

निःशुल्क साइकिल योजना तथा महिला छात्रावासों के निर्माण जैसी पहलों से भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन उपलब्ध कराने का उद्देश्य उन्हें तकनीक से जोड़कर ज्ञान और कौशल विकास के नए अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराने के लिए डीबीटी के माध्यम से धनराशि देने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के

बेहतर अवसर मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को शिक्षा के साथ कौशल विकास, नवाचार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रोन दीदी योजना के माध्यम से ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आलम्बन आर्ट, आलम्बन गांव और आलम्बन कैफे जैसी पहलों से जरूरतमंद महिलाओं और किशोरियों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही नव्या 2.0 के माध्यम से हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर की किशोरियों एवं युवतियों को कौशल विकास तथा उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों की शिक्षा के साथ उनकी सुरक्षा भी राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बाल विवाह और अन्य सामाजिक बुराइयों की रोकथाम के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अनाथ बच्चों के लिए राजकीय सेवाओं में पांच प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा पाँक्सो पीड़ित बच्चों को कानूनी सहायता एवं मानसिक देखभाल उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जनपद में सपोर्ट पर्सन की व्यवस्था की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की

मेहनत और प्रतिभा के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो, इसके लिए राज्य में कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। मुख्यमंत्री ने बालिकाओं से बड़े सपने देखने, निरंतर परिश्रम करने और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के संकल्प के साथ राज्य सरकार प्रत्येक बेटे को आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के माध्यम से मेधावी बालिकाओं को सम्मानित करने का उद्देश्य उनकी उपलब्धियों को प्रोत्साहन देने के साथ अन्य बेटियों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खजान दास, अपर सचिव कमेंड सिंह, निदेशक महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास बंशीलाल राणा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

गुलदार की दहशत से गुस्साए ग्रामीणों ने किया हाईवे जाम

श्रीनगर गढ़वाल (ब्यूरो)। बछेली के तरुली गांव में शुक्रवार को गुलदार के हमले में महिला की मौत के बाद शनिवार को ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर उतर आया। गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने खंडाह में श्रीनगर-पौड़ी राजमार्ग पर जाम लगा दिया।

करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने गुलदार को मारने के आदेश की जानकारी दी जिसके बाद ग्रामीण जाम खोलने को तैयार हुए। मौके पर पहुंचे डीएफओ पौड़ी महातिम यादव, उपजिलाधिकारी श्रीनगर नूपुर वर्मा और पुलिस उपाधीक्षक तपेश कुमार ने ग्रामीणों को समझाया। काफी देर तक ग्रामीणों और प्रशासन के मध्य तीखी नोकझोंक भी हुई। डीएफओ और उपजिलाधिकारी आदेश आने की बात करते रहे लेकिन ग्रामीण नहीं माने।

पुलिस उपाधीक्षक तपेश कुमार ने आक्रोशित ग्रामीण महिलाओं को जारी आदेश पढ़कर सुनाया और वन विभाग की ओर से की जा रही कार्रवाई की जानकारी दी। इसके बाद ग्रामीण सड़क से हटने को राजी हुए और यातायात बहाल हो सका।

वहीं ग्राम प्रधान कुलदीप गुसाई ने कहा कि पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए।

डीएफओ महातिम यादव ने बताया कि क्षेत्र में वन विभाग की दो टीमों लगातार गश्त कर रही हैं। प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव से गुलदार को पकड़ने और ट्रैकुलाइज करने के आदेश मिले हैं। यदि इन दोनों विकल्पों से गुलदार को काबू करने में सफलता नहीं मिलती है तो उसे नष्ट करने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके लिए क्षेत्र में दो शिकारी तैनात किए गए हैं। गुलदार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए छह ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, जबकि उसे पकड़ने के लिए दो पिंजरे भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से निर्धारित सहायता राशि का भुगतान कर दिया गया है। डीएफओ ने ग्रामीणों से वन विभाग की कार्रवाई में सहयोग करने की अपील भी की।

बीते शुक्रवार की घटना के बाद गुलदार क्षेत्र में लगातार दिखाई दे रहा है। शनिवार सुबह साढ़े छह बजे भी मृतका बीना देवी के घर के पीछे 100 मीटर की दूर पर गुलदार दिखाई दिया। वन विभाग की टीम के साथ पहुंचे प्रसिद्ध शिकारी जॉय हुकिल ने बताया कि गुलदार शनिवार सुबह भी मृतक बीना देवी के घर के पीछे जंगल में दिखाई दिया।

प्रेमनगर में 80वें विजयदशमी महोत्सव की तैयारियां शुरू, सौंपी गई जिम्मेदारियां

रिपोर्टर राजू ठाकुर

देहरादून। प्रेमनगर में आयोजित होने वाले 80वें भव्य विजयदशमी महोत्सव की तैयारी को लेकर प्रेमनगर दशहरा कमेटी ने एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जिसमें महोत्सव की तैयारियों, आयोजन की रूपरेखा और व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की गई।

बैठक में कमेटी के संयोजक राजीव पुंज (सत्री) ने उपस्थित सदस्यों को आयोजन की तैयारियों से अवगत कराते हुए सभी से आपसी सहयोग, समर्पण और एकजुटता के साथ महोत्सव को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयासों से इस ऐतिहासिक आयोजन को भव्य स्वरूप दिया जाएगा।

कमेटी ने कहा कि प्रेमनगर के लिए यह गौरव का विषय है कि यहां इस वर्ष 80वें विजयदशमी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वर्षों से चली आ रही यह परंपरा धार्मिक आस्था, सामाजिक एकता और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। इस



वर्ष भी महोत्सव का आयोजन प्रेमनगर दशहरा ग्राउंड में पारंपरिक रूप से किया जाएगा।

विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश देता है। प्रेमनगर में आठ दशकों से चली आ रही इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए दशहरा कमेटी के सदस्य तैयारियों में जुटे हुए हैं। कमेटी ने आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी सदस्यों से सक्रिय भागीदारी

निभाने की अपील की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रेमनगर दशहरा कमेटी के अध्यक्ष सूरज प्रकाश भाटिया के अलावा महेश शर्मा, राजेश शर्मा बाबू, किशोर लूथरा, फकीरचंद खेत्रपाल, विकी खन्ना, भूषण भाटिया, राजेश भाटिया, अमित भाटिया (डब्बू), रविंद्र सिंह खालसा, अमित भाटिया (मोनु), हरीश भाटिया, उमेश चावला, मोहित ग्रावर, मन्नु भाटिया, ललित शर्मा, रवि भाटिया और वंश मल्होत्रा सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

सम्पादकीय..



समेकित खेती से संवरता गांव

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए खेती को केवल पारंपरिक फसलों तक सीमित रखने के बजाय उसे बहुआयामी आजीविका से जोड़ना समय की मांग है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत केकराखोली में समेकित खेती की पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करती है। यहां सरकारी योजनाओं के समन्वित उपयोग से 25 किसानों की लगभग 35 एकड़ भूमि पर फलोद्यान, अंतरवर्ती फसलों और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह पहल बताती है कि उपलब्ध भूमि और संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग ग्रामीण समृद्धि के नए रास्ते खोल सकता है। कृषि के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आय की अनिश्चितता है। पारंपरिक खेती में किसानों की आमदनी मौसम, उत्पादन और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ऐसे में समेकित कृषि पद्धति किसानों को आय के विविध स्रोत उपलब्ध कराने में मदद कर सकती है। केकराखोली में आम और कटहल जैसे फलदार पौधों के साथ हल्दी, उड़द, करेला और बरबटी जैसी फसलों की खेती की जा रही है। सतावर और सिंदूरी जैसे औषधीय पौधों को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है। फलदार पौधों से उत्पादन मिलने में समय लगता है, लेकिन इस अवधि में अंतरवर्ती फसलें किसानों को आय का सहारा दे सकती हैं। इस तरह खेत का उपयोग अधिक प्रभावी बनाने के साथ उत्पादन के अलग-अलग अवसर भी तैयार होते हैं। इस मॉडल का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष कृषि संबंधी बुनियादी सुविधाओं का विकास है। खेतों की सुरक्षा के लिए फेंसिंग, सिंचाई के लिए बोरवेल और पौधों की सुरक्षा के लिए ग्रीन शेड हाउस जैसी सुविधाएं खेती को व्यवस्थित बनाने में सहायक हैं। हालांकि, इन संसाधनों का दीर्घकालिक लाभ तभी सुनिश्चित होगा, जब उनका उचित रखरखाव हो और किसान उन्हें उपलब्ध तकनीकी मार्गदर्शन के साथ इस्तेमाल कर सकें। कृषि योजनाओं की सफलता केवल सुविधाएं उपलब्ध कराने से नहीं, बल्कि उनके प्रभावी संचालन और किसानों की निरंतर सहायता से तय होती है। जल संरक्षण को आज कृषि की स्थिरता से अलग करके नहीं देखा जा सकता। केकराखोली में निर्मित सात आजीविका डबेरियां सिंचाई और जल संचयन के साथ मत्स्य पालन के अवसर भी उपलब्ध करा रही हैं। यह व्यवस्था जल संसाधनों के बहुउपयोग की संभावना दिखाती है। यदि जल उपलब्धता, स्थानीय परिस्थितियों और तकनीकी सलाह को ध्यान में रखकर ऐसी संरचनाओं का संचालन किया जाए, तो वे खेती के साथ अतिरिक्त आजीविका का माध्यम बन सकती हैं। केकराखोली की पहल का व्यापक महत्व सरकारी योजनाओं के अभिसरण में भी निहित है। जब कृषि, उद्यानिकी, जल संरक्षण और आजीविका से जुड़ी योजनाएं अलग-अलग काम करने के बजाय साझा उद्देश्य के साथ लागू होती हैं, तो उनके लाभ अधिक प्रभावी ढंग से किसानों तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, समय पर सहायता, गुणवत्तापूर्ण पौधों की उपलब्धता और उपज के विपणन की व्यवस्था भी जरूरी है। हालांकि, किसी भी कृषि मॉडल की वास्तविक सफलता का आकलन केवल खेती के क्षेत्रफल या सुविधाओं की संख्या से नहीं, बल्कि किसानों की आय, उत्पादन लागत, रोजगार और बाजार तक पहुंच में आए बदलाव से किया जाना चाहिए। केकराखोली में अपनाई गई समेकित खेती की पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए इन पहलुओं का नियमित मूल्यांकन आवश्यक होगा। साथ ही, सफल अनुभवों को दूसरे गांवों तक पहुंचाने से पहले वहां की मिट्टी, जलवायु, जल उपलब्धता और किसानों की जरूरतों का आकलन करना भी जरूरी है। स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास का टिकाऊ रास्ता खेती को लाभकारी, विविधतापूर्ण और संसाधन-संरक्षण पर आधारित बनाने से होकर गुजरता है। केकराखोली के 25 किसानों की पहल इस दिशा में संभावनाएं प्रस्तुत करती है। यदि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, तकनीकी सहयोग और बाजार की सुविधाएं साथ-साथ विकसित की जाएं, तो समेकित खेती किसानों की आजीविका को मजबूत करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक टिकाऊ आधार दे सकती है।

नई टिहरी में कनस्तर बजाकर विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस नेताओं समेत कई गिरफ्तार

नई टिहरी। जिला मुख्यालय नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर कांग्रेस जनों द्वारा बुधवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। राजकीय प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज नई टिहरी में राज्य सरकार के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आए सभी नेताओं के ठीक सामने नवदुर्गा मंदिर से कांग्रेस जनों द्वारा कनस्तर बजाकर जोरदार विरोध किया गया प्रदर्शन के दौरान स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल, स्थानीय विधायक किशोर उपाध्याय तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के दौरे के विरोध में कांग्रेसजनों और आंदोलनकारियों ने कनस्तर बजाकर

अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिला मुख्यालय नई टिहरी में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक ठोस पहल नहीं की गई है। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया कि मेडिकल कॉलेज टिहरी की जनता की बुनियादी स्वास्थ्य जरूरतों से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राकेश राणा, पूर्व राज्य मंत्री सैयद मुशर्रफ अली, पीसीसी सदस्य देवेंद्र नोडीयाल, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नवीन सेमवाल, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ

के प्रदेश सचिव इमरान खान, सोनू, छात्र नेता राहुल बुटोला, कांग्रेस नेता वीरेंद्र दत्त सहित कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आंदोलनकारियों ने मेडिकल कॉलेज की मांग के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े गंभीर सवालों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध जांच होनी चाहिए तथा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव राकेश राणा ने कहा कि वोट चोरी के आरोपों के

विषय बन जाता है। बढ़ी हुई वेतन सीमा के साथ, यह कवरेज सौदेबाजी का विषय न रहकर अधिकार बन जाएगी।

बढ़ी हुई वेतन सीमा कामगारों से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान तो नहीं करती, लेकिन यह औपचारिक सामाजिक सुरक्षा तंत्र को थोड़ा अधिक न्यायसंगत और थोड़ा व्यापक जरूर बनाती है। 10,000 रुपये की वृद्धि भले ही मामूली लगती हो, लेकिन अब सामाजिक सुरक्षा तंत्र के दायरे में आने वाले अतिरिक्त 51 लाख कामगारों की संख्या मामूली नहीं है। और अधिकांश अधिकारों के विपरीत, इस अधिकार का लाभ लेने के लिए कामगार को अपनी ओर से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है।

मनुष्य अपने भविष्य की कल्पना करने और उसके लिए तैयारी करने में खास अच्छे नहीं होते। 65 वर्ष की उम्र के अपने भावी स्वरूप के लिए कोई बजट नहीं बनाता। हम अक्सर उस छोटे लाभ को चुनते हैं जो जल्दी मिल जाए, बजाय उस बड़े लाभ के जो देर से मिले। व्यवहार अर्थशास्त्र में इसे हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग' कहा जाता है। परिणामस्वरूप, सीमित आय में तत्काल उपभोग की जरूरतों को पूरा करने की तुलना में भविष्य में अपने लिए या किसी भावी परिस्थिति के लिए बचत करना और योजना बनाना अक्सर अधिक कठिन होता है। यही कारण है कि ईपीएफओ द्वारा संचालित अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान जैसी व्यवस्थाओं की रूपरेखा महत्वपूर्ण है। यह बचत के लिए कामगार की इच्छा या इच्छाशक्ति पर निर्भर किए बिना काम करती है। आय के कामगार के खाते में पहुंचने से पहले ही पेंशन के लिए अंशदान अलग रख दिया जाता है—जो पैसा कभी दिखाई ही नहीं देता, उसे खर्च करना संभव नहीं होता। और धीरे-धीरे, हर महीने वेतन का एक छोटा हिस्सा अलग रखा जाता है, जिससे सेवानिवृत्ति निधि तैयार होती है, जिसका उपयोग आपातकाल में भी किया जा सकता है, साथ ही जीवन बीमा का कवरेज भी मिलता है—वह भी आपके अपनी ओर से बिना कोई अतिरिक्त प्रयास किए।

हालांकि, इस संशोधन के साथ नियोजकों के लिए एक लागत भी जुड़ी हुई है। अनिवार्य वेतन सीमा अब बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने के साथ, नियोजकों को काफी अधिक संख्या में कर्मचारियों को वैधानिक ईपीएफ कवरेज प्रदान करनी होगी और उनके मासिक अंशदान संबंधी दायित्व भी बढ़ जाएंगे।

बीच बनी सरकार अब तानाशाही पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सभी सांसदों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वह निंदनीय है। लोकतंत्र में इस तरह की कृतियों की कोई जगह नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि टिहरी की जनता अपने अधिकारों और क्षेत्र की बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करती रहेगी। जब तक जिला मुख्यालय नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

उदाहरण के लिए, 22,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला ऐसा कर्मचारी, जो पहले अनिवार्य कवरेज से बाहर था, अब वैधानिक रूप से ईपीएफ कवरेज के दायरे में आएगा और नियोजकों के लिए इस कर्मचारी को ईपीएफ कवरेज प्रदान करना अनिवार्य होगा। अब नियोजकों को वेतन का 12 प्रतिशत अंशदान करना होगा, जो ईपीएस पेंशन योजना और कर्मचारी के अपने ईपीएफ खाते के बीच विभाजित होगा। यह राशि प्रति कर्मचारी प्रति माह 2,640 रुपये या वार्षिक 31,680 रुपये होगी। ऐसे 20 कर्मचारियों के मामले में, यह अतिरिक्त पेंशन लागत के रूप में प्रति वर्ष 6,33,600 रुपये होगी। इसके अलावा, ईडीएलआई बीमा अंशदान भी होगा, जो राशि में भले ही छोटा है, लेकिन अब इसकी गणना भी अधिक वेतन आधार पर की जाएगी। नियुक्ति संबंधी निर्णय लेते समय यह नियोजकों के लिए एक वास्तविक लागत है।

अधिक लागत कंपनी के लिए एक स्पष्ट निष्कर्ष प्रतीत होती है, लेकिन यह केवल प्रारंभिक प्रभाव है और रोजगार बाजार इससे कहीं अधिक जटिल है। अधिक ईपीएफ कवरेज भर्ती के लिए एक सकारात्मक संकेत के रूप में काम करता है, जिससे अधिक कुशल और अधिक कार्य-क्षमता वाले कामगार आकर्षित होते हैं, क्योंकि नए कर्मचारी किसी नौकरी का मूल्यांकन करते समय केवल मासिक वेतन को ही ध्यान में नहीं रखते। यह कवरेज कर्मचारियों को लंबे समय तक बनाए रखने में भी सहायक हो सकती है। पेंशन और बीमा लाभ वाला कामगार संभवतः अधिक समय तक काम पर बना रहेगा और नौकरी की शुरुआत थोड़ी अधिक सुरक्षा के साथ करेगा। दूरदर्शी नियोजकों पहले से ही इसे समझते हैं और अच्छी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए स्वेच्छिक कवरेज प्रदान करते हैं। सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा यह है कि यह ट्रेम्पोलीन की तरह न केवल आपको संभालती है, बल्कि फिर से उछलकर आगे बढ़ने में भी सक्षम बनाती है। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य कामगारों को ऐसा कोष उपलब्ध कराना है, जिससे वे आपातकाल के समय या सेवानिवृत्ति के बाद आवश्यकता पड़ने पर धन प्राप्त कर सकें, जिससे कोई अस्थायी संकट जीवनभर की कठिनाई का रूप न ले और उन्हें ऋण-जाल में न फंसाए।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी पहलें, जिन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक किफायती और सुलभ बनाया है, इस सुरक्षा तंत्र को और मजबूत बनाती हैं। बदलते रोजगार स्व रूप हेतु तैयारी करने के लिए मजबूत उद्योग संपर्कों के साथ, कौशल उन्नयन, पुनःकौशल विकास और नव कौशल विकास के लिए कौशल विकास पारितंत्र का निर्माण किया जा रहा है। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) अंशदायी पेंशन कवरेज को उन लोगों के लिए कम आय वर्ग तक और आगे बढ़ाती है, जो निवेश जोखिम उठाने और आर्थिक तथा बाजार वृद्धि के लाभों में भागीदारी के इच्छुक हैं। यह ट्रेम्पोलीन भी कदम दर कदम मजबूत होता जा रहा है।



बॉक्स ऑफिस पर 'दृश्यम 3' का जलवा, 8 दिन में 400 करोड़ पार

अभिनेता अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 'बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के आठ दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 407 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने भारतीय सिनेमाघरों से 14.50 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि विदेशों से छह करोड़ रुपये मिले। इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल कारोबार 312 करोड़ रुपये और विदेशों में कमाई 95 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। 'दृश्यम 3' ने रिलीज से पहले ही अग्रिम टिकट बुकिंग के जरिए 27 करोड़ रुपये की कमाई की थी। फिल्म ने पहले सप्ताह में भी अच्छा प्रदर्शन किया। शनिवार को फिल्म ने 53.50 करोड़ रुपये और रविवार को 61 करोड़ रुपये कमाए। पहले सप्ताह में फिल्म की भारत में शुद्ध कमाई 245.50 करोड़ रुपये बताई गई है। फिल्म को सिनेमाघरों में दर्शकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार, दृश्यम 3 'हिंदी फिल्मों में अब तक की तीसरी सबसे बड़ी शुरुआती कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। फिल्म की कहानी और अजय देवगन के अभिनय को लेकर दर्शकों में उत्साह बना हुआ है। आठ दिनों में 407 करोड़ रुपये का वैश्विक कारोबार फिल्म के व्यावसायिक प्रदर्शन को दर्शाता है। अब फिल्म की कमाई पर दर्शकों और फिल्म उद्योग की नजर बनी हुई है।

संदीपा धर ने आतिश कपाड़िया को दिया कॉमेडी से परिचय कराने का श्रेय

नेटफ्लिक्स की चुंबक अपने मजेदार किरदारों और हल्के-फुल्के हास्य के कारण दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। शो में संदीपा धर, किरण का किरदार निभा रही हैं, जो बाकी अजीबोगरीब किरदारों के बीच बेहद समझदार हैं। शो का हिस्सा बनने के बारे में बात करते हुए संदीपा ने कहा, एक दिन मुझे चुंबक के निर्देशक आतिश कपाड़िया का फोन आया और उन्होंने बताया कि वे नेटफ्लिक्स और जेडी के साथ मिलकर एक नया शो बना रहे हैं। ऐसे में उन्होंने मुझे इसके लिए टेस्ट देने को कहा। उनकी बात सुनकर पहले तो मैं हैरान रह गई कि कॉमेडी और मैं ? क्योंकि मैंने पहले कभी कॉमेडी नहीं की थी। लेकिन उनकी बात सुनकर मैंने हामी भर दी। संदीपा ने आगे बताया, इसके बाद जब मेरी मुलाकात आतिश कपाड़िया से हुई तो उन्होंने जिस अंदाज में मुझे पूरी कहानी सुनाई, वो उससे भी ज्यादा मजेदार था। उन्होंने जिस तरह हर किरदार को खुद निभाकर दिखाया, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई नाटक देख रही हूँ। उसी समय मैंने तय कर लिया कि मुझे इस शो का हिस्सा बनना ही है।



भूमि पेडनेकर के साथ शानदार वापसी करेंगे इमरान खान, साल के अंत में होगा धमाका

अभिनेता इमरान खान सालों तक इंडस्ट्री से दूर रहने के बाद अब एक शानदार वापसी करने के लिए तैयार हैं। उनकी नई फिल्म अधूरे हम अधूरे तुम 2026 की शुरुआत में रिलीज होने वाली थी, जिसमें उनके साथ भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिका में रहने वाली हैं। हालांकि, अभिनेता ने खुलासा किया है कि ये फिल्म अब दिसंबर में क्रिसमस के आसपास रिलीज हो सकती है। इमरान की इस फिल्म का उनके प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इमरान खान ने बताया, हमें जानकारी मिली है कि निर्माता इसे 18 दिसंबर के आसपास रिलीज करना चाहते हैं, इसलिए हम पोस्ट-प्रोडक्शन का काम तेजी से निपटा रहे हैं ताकि समय पर फिल्म सौंप सकें। चूंकि ये फिल्म सिनेमाघरों के बजाय ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी, इसलिए तारीख से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आखिरकार

हम यह फिल्म दर्शकों के सामने ला पा रहे हैं। अधूरे हम अधूरे तुम से इमरान करीब 11 साल बाद बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। इससे पहले उन्हें 2015 में रिलीज होने वाली फिल्म कट्टी-बट्टी में देखा गया था।



इस नई फिल्म के जरिए इमरान 2010 में आई ब्रेक के बाद के बाद एक बार फिर निर्देशक दानिश असलम के साथ काम कर रहे हैं। अभिनेता मानते हैं, यह वो फिल्म है, जिसे हमें 16 साल बाद बनाना ही चाहिए था।

भाषा से भावना व्यक्त करने के तरीके में बदलाव आता है, बा बा ब्लैक शीप की मालवी मल्होत्रा

लुगु क्राइम-कॉमेडी फिल्म बा बा ब्लैक शीप में अभिनेत्री मालवी मल्होत्रा रमा के किरदार में नजर आ रही हैं। साउथ इंडस्ट्री में काम करने पर अभिनेत्री ने कहा कि भाषा इस बात को भी दिखाती है कि आप अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने कैसे व्यक्त करते हैं। अभिनेत्री ने कहा, हर इंडस्ट्री की काम करने की संस्कृति, लय और कहानी कहने की भाषा होती है और मेरे लिए इससे परिचित होना मददगार है। भाषा सिर्फ शब्दों या उच्चारण के बारे में नहीं है बल्कि, यह दिखाती है कि आप अपने मन की भावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, सीन की लय कैसी होती है और आप अपने सह-कलाकार को कैसे सुनते हैं। आखिरकार, भावनाएं सार्वभौमिक होती हैं। चाहे आप हिंदी, तेलुगु, तमिल या मलयालम बोल रहे हों, किरदार की सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस समझ ने मुझे और अधिक सहज और बहुमुखी कलाकार बना दिया है। अभिनेत्री ने रमा के किरदार के बारे में बताते हुए कहा, रमा की अपनी अलग पहचान और इमोशनल सफर है। मुझे यह पसंद आया कि उसे सिर्फ हीरो के आसपास या उसकी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिखा गया। उसके कई पहलू हैं और जहां कुछ पहलू वास्तविकता के करीब थे, वहीं कुछ ने मुझे अपने व्यक्तित्व से बाहर ला दिया। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया, वह था उसे एक असली इंसान जैसा महसूस कराने का अवसर, जिसमें उसके अपने विचार, कमजोरियां और ताकतें हों।

अपनी भूमिका की तैयारी के बारे में बताते हुए मालवी ने कहा, मैं आमतौर पर किरदार के बारे में ज्यादा कुछ तय नहीं करती, जब तक कि मैं यह न समझ लूं कि वह किस दुनिया से आती है, क्या चाहती है, किससे डरती है और किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। मैंने स्पष्ट हावभाव बनाने के बजाय अपने अभिनय को सहज बनाने की कोशिश की थी। मेरी थिएटर ट्रेनिंग ने मुझे सिखाया है कि छोटी-छोटी बातें किसी किरदार को विश्वसनीय बना सकती हैं,



इसलिए मैंने उसके आंतरिक जीवन पर अधिक ध्यान दिया और हावभाव को स्वाभाविक रूप से उभरने दिया। उन्होंने कहा, मुझे तुरंत जिस चीज ने आकर्षित किया था, वह कहानी और उसकी दुनिया थी। मैं ऐसे प्रोजेक्ट खोजती हूँ जहां पात्रों की अपनी यात्राएं

हों और कुछ सार्थक योगदान हो। जब मैंने पटकथा पढ़ी, तो मुझे लगा कि पात्र और उनकी भावनाएं कहानी को चला रही हैं। मैं सिर्फ पैमाने या ग्लैमर के कारण किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने से ज्यादा अच्छी कहानी का हिस्सा बनना पसंद करती हूँ।

करण जौहर का कॉफी विद करण के बाद नया धमाका, नए चैट शो से करेंगे वापसी

कॉफी विद करण का नौवां सीजन इसका आखिरी सीजन होगा। ये ऐलान खुद करण जौहर ने जियो हॉटस्टार पर कर दिया था, लेकिन क्या एक चैट शो होस्ट के रूप में ये उनका आखिरी सफर है? बिल्कुल नहीं। खबर है कि करण एक बिल्कुल नए चैट शो को लॉन्च करने की तैयारी में हैं। जब कमान करण के हाथों में है, तो जाहिर है कि इसमें बॉलीवुड का स्टाइल, चमक-धमक और चटपटी खबरों का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक, करण अपना नया शो लाना चाहते हैं।



दरअसल, कॉफी विद करण नाम के अधिकार उनके पास नहीं बल्कि जियो हॉटस्टार के पास हैं। कहा जा रहा था कि करण फिल्म निर्देशन पर ध्यान देने के लिए ये शो बंद कर रहे हैं, लेकिन असली वजह ये है कि वो पूरी तरह से अपना नया शो बनाना चाहते हैं, जिसे वो पहले यूट्यूब पर रिलीज करेंगे और फिर किसी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेचेंगे। हाल-फिलहाल करण का पूरा ध्यान कॉफी विद करण 9 पर है। इस आखिरी सीजन के लिए उन्होंने बॉलीवुड के दिग्गज सितारों को एक साथ जुटाया है। सूत्रों के मुताबिक, सलमान खान ने गुरुवार को अपने एपिसोड की शूटिंग पूरी कर ली है। चर्चा है कि शो की शुरुआत या तो सलमान खान करेंगे या फिर आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल। यही नहीं, पहली बार शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान भी एक साथ शो में नजर आएंगे।

आस्था, संस्कृति और आधुनिक संचार माध्यमों के जरिए देश-दुनिया तक पहुंचेगा कुंभ का संदेश



हरिद्वार (ब्यूरो)। हरिद्वार कुंभ मेला-2027 की धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ के आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और गीत का लोकार्पण किया। इन तीनों माध्यमों के जरिए कुंभ की विशिष्ट पहचान को देश-दुनिया तक पहुंचाने, आयोजन से संबंधित सूचनाओं को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने और कुंभ के आगमन का संदेश जन-जन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है।

सोमवार को मेला नियंत्रण भवन (सीसीआर) सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ-2027 के आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और गीत का लोकार्पण करते हुए कहा कि कुंभ भारत की प्राचीन आध्यात्मिक परंपरा, सनातन

संस्कृति और जनआस्था का विराट उत्सव है। हरिद्वार कुंभ का करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए विशेष धार्मिक महत्व है। राज्य सरकार कुंभ मेला-2027 के दिव्य एवं भव्य आयोजन के लिए प्रतिबद्ध है। आयोजन को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। उन्होंने कहा कि आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और गीत कुंभ की पहचान को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के साथ श्रद्धालुओं और आमजन को इससे जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

लोगो में समाहित हरिद्वार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत

हरिद्वार कुंभ-2027 का आधिकारिक लोगो हरिद्वार की धार्मिक पहचान, गंगा के प्रति श्रद्धा और सनातन परंपरा की विशेषताओं को एक साथ दर्शाता है। इसमें

मां गंगा, हर की पैड़ी क्षेत्र, धनुष पुल और सूर्योदय की दिव्य छटा को दर्शाया गया है। साथ ही शिव प्रतिमा, साधु-संतों, सनातन परंपरा के प्रतीक त्रिशूल एवं डमरू तथा मां मनसा देवी और मां चंडी देवी की पहचान को भी स्थान दिया गया है।

लोगो में समाहित ये प्रतीक हरिद्वार की आध्यात्मिक महत्ता और कुंभ की सांस्कृतिक विरासत को अभिव्यक्त करते हैं। इसका उपयोग आयोजन से संबंधित प्रचार सामग्री, प्रकाशनों और डिजिटल मंचों पर किया जा सकेगा। इससे कुंभ की दृश्य पहचान को एकरूपता के साथ प्रस्तुत करने और आयोजन के प्रचार-प्रसार को व्यवस्थित स्वरूप देने में मदद मिलेगी।

कुंभ मेला-2027 का लोगो डिजाइन करने के लिए मेला प्रशासन द्वारा राज्य के युवाओं एवं विद्यार्थियों से प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थीं। प्राप्त सैकड़ों प्रविष्टियों में से 13 श्रेष्ठ एवं मौलिक डिजाइनों पर चयन समिति ने विचारकरने के बाद विकास नगर, जगजीतपुर, हरिद्वार निवासी मधु शर्मा द्वारा प्रस्तुत सर्वश्रेष्ठ डिजाइन का चयन किया। इसी डिजाइन के आधार पर हरिद्वार कुंभ-2027 के आधिकारिक लोगो को अंतिम रूप दिया गया।

आधिकारिक वेबसाइट से कुंभ संबंधी सूचनाओं तक होगी आसान पहुंच

कुंभ मेला-2027 की आधिकारिक वेबसाइट <https://haridwarkumbh.uk.gov.in> के

माध्यम से श्रद्धालुओं, आगंतुकों और आमजन तक कुंभ से संबंधित प्रामाणिक जानकारी पहुंचाई जा सकेगी।

डिजिटल मंच पर सूचनाओं की उपलब्धता से आयोजन संबंधी जानकारी को व्यवस्थित ढंग से प्रसारित करने और देश के विभिन्न हिस्सों के साथ विदेशों में रहने वाले श्रद्धालुओं को भी कुंभ से जोड़ने में मदद मिलेगी। यह माध्यम कुंभ की तैयारियों और आयोजन से जुड़ी जानकारियों तक लोगों की पहुंच सुगम बनाने के साथ हरिद्वार की धार्मिक पहचान को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने में उपयोगी होगा।

‘कुंभ का पर्व आ गया’ गीत में झलकेगा आस्था और उल्लास

कुंभ मेला-2027 के आधिकारिक गीत का लोकार्पण समारोह का प्रमुख आकर्षण रहा। ‘साधु और संतों के मन में हर्ष छा गया, कुंभ का पर्व आ गया’ पंक्तियों से शुरू होने वाला यह गीत कुंभ के आगमन की प्रसन्नता, साधु-संतों के उत्साह और श्रद्धालुओं की आस्था को स्वर देता है। इस गीत की रचना, गायन और संगीत हरिद्वार निवासी गायक राघव राजा ने किया है।

गीत के माध्यम से कुंभ के आगमन का संदेश जन-जन तक पहुंचाने और आयोजन के प्रति सांस्कृतिक जुड़ाव को मजबूत करने का उद्देश्य है। धार्मिक आयोजनों में गीत-संगीत जनभावनाओं

की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम रहा है।

परंपरा की गरिमा के साथ आधुनिक संचार माध्यमों का समन्वय

हरिद्वार कुंभ-2027 उत्तराखंड की आध्यात्मिक विरासत, धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पहचान को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। आधिकारिक लोगो आयोजन को विशिष्ट दृश्य पहचान प्रदान करेगा, वेबसाइट सूचना के डिजिटल प्रसार का माध्यम बनेगी और गीत कुंभ के आगमन से जुड़ी भावनाओं को अभिव्यक्त करेगा। तीनों माध्यमों के समन्वित उपयोग से कुंभ की धार्मिक महत्ता, सांस्कृतिक वैभव और परंपराओं को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

लोकार्पण समारोह में कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे उपस्थित

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा एवं राम सिंह कैड़ा सहित मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, एसएसपी नवनीत भुल्लर, महानिदेशक सूचना वंशीधर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र, अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती, अपर जिलाधिकारी जितेन्द्र कुमार तथा उप मेलाधिकारी आकाश जोशी एवं मनजीत सिंह सहित मेला एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

13 पदों के सृजन के साथ सीएचसी बना ऊखीमठ स्वास्थ्य केंद्र, शासनादेश जारी

रुद्रप्रयाग (नि०स०)। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ को 13 पदों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उच्चिकृत करने का शासनादेश जारी हो गया है। वर्षों पुरानी मांग पूरी होने पर प्रधान संगठन, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए राज्य सरकार और केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल का आभार व्यक्त किया है।

शासनादेश के अनुसार, स्वास्थ्य केंद्र के उच्चिकरण के तहत चिकित्सा अधीक्षक, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट व अन्य विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, फिजिशियन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, निश्चेतक, चिकित्सा अधिकारी और दंत चिकित्सक सहित पैरामेडिकल एवं प्रशासनिक स्टाफ के पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पारूल गोयल ने बताया कि शासनादेश जारी होने के बाद सीएचसी के मानकों के अनुरूप आवश्यक उपकरणों एवं सामग्री की सूची तैयार की जा रही है। साथ ही

चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था करने की मांग निदेशालय को भेजी जा रही है। ज्येष्ठ प्रमुख राकेश नेगी, प्रधान संगठन के संरक्षक मनवर नेगी, महामंत्री मदन भट्ट, उपाध्यक्ष विनोद नेगी, महेंद्र सेमवाल, जिला संगठन सदस्य अनीता देवी और सरिता देवी ने कहा कि विधायक आशा नौटियाल के प्रयासों से क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। शासनादेश जारी होने के बाद शनिवार को विधायक आवास पर जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस अवसर पर ग्राम प्रधान सुलेखा त्रिवेदी, विशाम्बरी देवी, नीमा देवी, सभासद बलवीर पंवार, मधुगंगा ग्रुप के चेयरमैन कुशल सिंह नेगी, दर्शनी पंवार, भाजपा मंडल अध्यक्ष दलवीर नेगी, किरन शुक्ला, जगदीश लाल, शिक्षाविद् भूपेंद्र राणा, प्रताप धर्म्बाण, योगेंद्र राणा, शिव सिंह पंवार सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

फर्जी प्रमाण पत्र मामले: देहरादून कलेक्ट्रेट का सरकारी जनाधार केंद्र बंद, 3 कर्मचारी भी हटाए

देहरादून (नि०स०)। उत्तराखंड में फर्जी प्रमाण पत्रों से एमबीबीएस सीट आवंटन के मामले में जांच के बीच देहरादून कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सरकारी जनाधार केंद्र बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने केंद्र में तैनात तीनों कर्मचारियों को हटा दिया है।

जांच पूरी होने के बाद नए कर्मचारियों की तैनाती कर केंद्र दोबारा खोला जाएगा। उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एमबीबीएस सीट आवंटन का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने एक गिरोह का पर्दाफाश किया था। जांच में पता चला कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित बनकर फर्जी आश्रित प्रमाण पत्र बनवाए गए थे। ये प्रमाण पत्र देहरादून के जनाधार केंद्र से

जारी हुए थे। मामले में डीएम डॉ. आशीष चौहान ने दो पटवारियों को निलंबित किया था और केंद्र के तीन कर्मचारियों को हटा दिया था। वहीं, संबंधित प्रमाण पत्र निरस्त किए गए हैं। डीएम डॉ. चौहान ने केंद्र बंद किए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच के दौरान कर्मचारियों को हटाने के कारण इसे कुछ समय के लिए बंद किया गया है।

दून-यूएसनगर फर्जी प्रमाणपत्र के ‘हॉटस्पॉट’

देहरादून के सदर क्षेत्र से तीन प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए थे, जबकि यूएसनगर के गदरपुर से नौ प्रमाणपत्र फर्जी मिले। बाकी तहसीलों से तीन प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए।

हेमकुंड साहिब के कपाट बंद: बर्फबारी के बीच साल की अंतिम अरदास, ऐतिहासिक पल के साक्षी बने श्रद्धालु

चमोली (ब्यूरो)। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे हेमकुंड साहिब में साल की अंतिम अरदास के साथ दर्शन का सिलसिला शीतकाल के लिए थम गया। इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पवित्र धाम पहुंचे। कपाट बंद होने के ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए पाकिस्तान से आए 40 सदस्यीय सिख श्रद्धालुओं के जत्थे समेत हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे।

सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब के कपाट आज शनिवार को साल की अंतिम अरदास के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इस वर्ष धाम में रिकॉर्ड 3,84,573 से अधिक श्रद्धालुओं ने मत्था टेका। कपाट बंद होने के ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए करीब चार हजार श्रद्धालु मौजूद रहे। पाकिस्तान से आए 40 सदस्यीय सिख श्रद्धालुओं के जत्थे ने भी इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बर्फबारी के बाद सफेद चादर में लिपटे धाम तक श्रद्धालु बर्फाले रास्तों से पहुंचे और अंतिम अरदास में शामिल हुए।

अब सवाल सिर्फ मेडिकल अभ्यर्थियों पर ही नहीं है, बल्कि प्रमाणपत्र जारी

तहसील सदर से पत्रावली की चोरी में 2 साल बाद एफआईआर

तहसील सदर न्यायालय से जरूरी दस्तावेज गायब होने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने दो साल बाद मुकदमा दर्ज किया है। हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोप था कि दस्तावेज वर्ष 2019 में गायब हुए थे। इस मामले में नवंबर 2024 में तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय गुमशुदगी दर्ज की थी। तहसीलदार सदर न्यायालय की ओर से पुलिस को दी तहरीर में बताया गया कि न्यायालय से कुछ जरूरी दस्तावेज गायब हो गए थे। इस संबंध में आठ नवंबर 2024 को मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थनापत्र दिया गया था। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत पर गुमशुदगी तो दर्ज कर ली, लेकिन चोरी का मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने पत्रावली गायब होने के संबंध में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।



कपाट बंद होने से एक दिन पहले शुक्रवार को हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हुई जिससे पूरा धाम बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। सीजन की अंतिम अरदास के साथ कपाट बंद करने की प्रक्रिया पूरी हुई। श्रद्धालुओं को बर्फ से ढके हेमकुंड साहिब के मनमोहक नजारे का दीदार करने का मौका भी मिला।

सेना के बैंड की मधुर धुनों के बीच करने वाली पूरी व्यवस्था पर भी खड़ा हो चुका है।

पंज प्यारों की अगुवाई में गुरु ग्रंथ साहिब को दरबार साहिब से सचखंड में सुशोभित किया गया। इसके बाद हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने से ठीक पहले हुई बर्फबारी ने धाम की खूबसूरती और बढ़ा दी है। हेमकुंड साहिब के साथ ही लोकपाल घाटी के अन्य धार्मिक स्थलों के कपाट बंद होने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लक्ष्मण मंदिर के कपाट रविवार को बंद किए जाएंगे। मंदिर के पुजारी मनीष पांडे ने बताया कि कपाट बंद करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

स्वामी, प्रकाशक व सम्पादक दीपक कुमार सहगल द्वारा मुद्रक रजत शर्मा, अभिप्रेरणा प्रिन्टर्स, पो.ऑ. बंजारावाला, कारगी, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001 से मुद्रित करकर 9/21 मोहित विहार, गुरुद्वारे के पीछे जी.एम.एस रोड, कांवली रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड-248001 से प्रकाशित।

सम्पादक:- दीपक कुमार सहगल
मो.- 8755065050

E-MAIL ID : sehgal.deepak1@gmail.com

नोट:- सभी विवादों का न्यायिक क्षेत्र देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा।